(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ; और

[illegible]
के लिये सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये हैं तथा उठाने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) और (ख) तम्बाकू के उपयोग से आमतौर पर विभिन्न प्रकार के कैंसर जाते हैं जैसे मुख-[illegible] और ग्रासनली का भारत में तम्बाकू जैसे कैंसर, हृदयवा[illegible] की बीमारियों से [illegible] लोग मर जाते हैं। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि मद्यपान करने वालों में मुख कविटी, स्वरयंत्र, [illegible] और मलाशय तथा का अधिक खतरा रहता है।

मद्यपान [illegible] सीधा संबंध पेशियों पर दबाव कठिन्य की गति [illegible] का दौरा पड़ जाता है।

(ग) धूमपान और मद्यपान करने के बुरे प्रभावों के बा[illegible] कारी देने के लिये सरकार द्वारा दूरदर्शन, रेडि[illegible] फिल्मों, समाचार पत्रों, पम्पलेट्स आदि जैसे सभी जन प्रचार माध्यमों के जरिये व्यापक स्वास्थ्य शिक्षा क्रियाकलाप शुरू किये गये है।

योग विश्वविद्यालय की स्थापना

1074. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की [illegible] पा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को योग-विश्व-विद्यालय स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव-पत्र और सुझाव प्राप्त हुये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा ये पत्र और सुझाव किस से प्राप्त हुये हैं तथा इनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) दिल्ली के आस-पास अथवा देश के अन्य भागों में योग विश्वविद्यालय [illegible] करने के लिये सरकार भूमि के [illegible] अन्य क्या सुविधायें देगा ; और

(घ) देश में ऐसे विश्वविद्यालय की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है ?

मानव संसाधन मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री [illegible] साही) : (क) और (ख) सरकार ने, 1986 में दिल्ली में आयोजित प्रथम विश्व योग सम्मेलन द्वारा [illegible] एक संकल्प फरवरी, 1987 में प्राप्त हुआ था, जिसमें भारत सरकार से राजधानी के समीप एक केन्द्रीय यो[illegible] स्थापना करने का अनुरोध [illegible] । संकल्प में सभी राज्य सरकारों से भी प्रत्येक जिले में योग कालेज स्थापित करने का अनुरोध किया गया था, जो [illegible] से संबद्ध होना चा[illegible]

(ग) और (घ) विश्व योग सम्मेलन के अध्यक्ष को यह सूचित किया था कि केन्द्रीय सरकार के पास केवल योग को बढ़ावा देने के लिये एक विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में योग सहित शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा और खेलों में एक 3 वर्ष का पाठ्यक्रम शुरू करने की एक योजना तैयार की है तथा आयोग ने भी विश्वविद्यालयों से अनुरोध किया है कि वे कम से कम प्रत्येक जिले के एक मौजूदा कालेज में इसे शुरू करने पर विचार करें। आयोग ने इस पाठ्यक्रम को आरम्भ करने के लिये इस योजना अवधि में लगभग 12.50 लाख रुपये की सीमा तक वित्तीय सहायता देने की पेशकश की थी। विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिये न तो सरकार और न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करता है, जो कि साधारणतः राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने विधानमंडलों के अधिनियमों के अन्तर्गत

स्थापित किये जाते हैं तथा वे अपने अपने संसाधनों से निधियां प्रदान करते हैं। [illegible] प्रदान आयोग द्वारा राज्य [illegible] दी गई सहायता केवल विकास प्रयोजनो के लिये ही है।

योग शिक्षा का शुरू किया जाना

1075. श्री [illegible] विकल : क्या मा[illegible] संसा[illegible] बताने की कृपा करेंगे कि :

[illegible] देने हेतु स्कूलों और कालेजों में योग [illegible] आरम्भ किये जाने के लिये सरकार को 1 जनवरी, 1987 और 15 जुलाई, 1988 के बीच कुल [illegible] व्यक्तियों तथा संस्थाओं से [illegible] आदि प्राप्त हुये है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम प्राप्त हुये

(घ) समस्त देश में योग शिक्षा आरम्भ करने के लिये सरकार की क्या योजना है तथा इसे कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साही) : (क) और (ख) योग शिक्षा शुरू करने के बारे में पिछले एक वर्ष से विभिन्न स्रोतों से अशंदान सुझाव प्राप्त हुये है। अन्य बातों के साथ-साथ यह भी सुझाव दिया गया है कि स्कूलों में योग शुरू करने, योग शिक्षकों के लिये उपयुक्त पाठ्यचर्या, प्रशिक्षण आदि का विकास करने के लिये आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये ;

(ग) और (घ) विभिन्न स्कूलों में योग शिक्षा शुरू करने के लिये एक योजना सरकार के विचाराधीन है।

Introduction of three language formula in Central Schools

1076. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI T. R. BALU:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to implement strictly the three language formula in all the Central Schools in the country from the next academic Session; if so, what are the details of the scheme in this regard and which languages have been selected for the

(b) whether it is a fact that Hindi speaking State have not shown sufficient interest in implementing this formula;

(c) by when all the Central Schools are expected to offer three languages students;

(d) what would be the estimated expenditure in this regard in the next three years; and

(e) what efforts are being made by Government to remove the financial constraints being faced by the State Governments in implementing the said formula?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF EDUCATION AND CULTURE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI L. P. SAHI): (a) It has been decided to introduce the Three Language Formula in all Kendriya Vidyalayas with effect from 1988-89 Session. Under this formula, a modern Indian language, preferably one of the southern languages, Hindi and English will be taught in Kendriya Vidyalayas in the Hindi speaking States and the concerned regional language, Hindi and English will be taught in Kendriya Vidyalayas in non-Hindi speaking States.

(b) In the implementation of three language formula in the Kendriya Vidyalaya Sangathan, the states are not involved.